

THE
PARLIAMENTARY DEBATES
OFFICIAL REPORT

IN THE NINETY-FIRST SESSION OF THE RAJYA SABHA
commencing on the 11th February, 1975/the 25th Magha, 1896 (Saka)

1

RAJYA SABHA

*Monday, the 11th February, 1975/the 28/A
Magha, 1896 (Saka)*

The House met at twenty five minutes past twelve of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

PRESIDENT'S ADDRESS

SECRETARY-GENERAL : I lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the President's Address to both the Houses of Parliament assembled together on the 17th February, 1975.

माननीय सदस्यगण, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और अगले वर्ष फिर मेहनत और लगन के साथ राष्ट्र की सेवा करने का बुलावा देता हूँ।

पिछले चार वर्षों में नागहानी और भारी चुनौतियों का हिम्मत से मुकाबला करने के बाद हम बड़े साहस के साथ यह वर्ष शुरू कर रहे हैं। लगातार बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए 1974 में सरकार की सबसे बड़ी चिन्ता यह रही कि अर्थ-व्यवस्था को पायदार बनाया जाए। मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए सरकार ने एक व्यापक नीति अपनाई और जुलाई 1974 से इसे अमल में लाया गया।

अधिक से अधिक साधन जुटाने और गैर-योजना खर्च में कमी करने के अलावा, एक उचित मुद्रानीति के जरिये मुद्रा-प्रसार पर रोक लगाई गई। स्मगलिंग, जमाखोरी और टैक्स इवेजन जैसे आर्थिक अपराधों तथा कम मिलने वाली चीजों का नकली माल बनाने वालों के खिलाफ एक जोरदार मुहिम चलाई गई। डिविडेंड्स की आमदन को सीमित करके और बढ़ाई गई मजदूरी, वेतन और मंहगाई भत्ते के एक हिस्से को

2

रोके रख कर कन्स्यूमर खर्च को काबू में रखा गया। सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत किया गया और अनाज, जरूरी कच्चा माल और दूसरे सामान को काफी मात्रा में आयात करने का बन्दो-बस्त किया गया। 1974-75 की सालाना योजना पर फिर से गौर किया गया और उत्पादन बढ़ाने की गर्ज से जरूरी क्षेत्रों में खर्च की जाने वाली रकम को बढ़ाया गया। पावर प्लांट्स, रेल ट्रांसपोर्ट, कोयला उत्पादन इस्पात प्लांट्स और दूसरे सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों की क्षमता को पूरी तरह काम में लाने के लिये जोरदार कार्रवाई की गई।

इन सब कार्रवाइयों के नतीजे सितम्बर, 1974 के आखिर में सामने आने शुरू हुए। कई राज्यों में वर्षा की कमी की वजह से खरीफ की फसल तसल्लीदृश न होते हुए भी कीमते गिरनी शुरू हुई और मुद्रा-स्फीति को बढ़ावा देने वाले जरिये कमजोर पड़ने लगे। जरूरियाते जिदगी की चीजों के मिलने में सुधार हुआ है और रबी की फसल अच्छी होने के आसार हैं।

इस माली साल के पहले नौ महीनों में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादन में अच्छी बढ़ोत्तरी हुई है। थर्मल प्लांट्स से चौदह फ्रीसदी ज्यादा बिजली पैदा की जा रही है और डी०वी०सी० प्लांट्स से बिजली पैदा करने में चौतीस फ्रीसदी की बढ़ोत्तरी काबले जिकर है। क्योंकि कई राज्यों में फिर भी बिजली की कमी पाई जाती है। पावर प्रोजेक्ट्स के पूरा करने के काम को जोरों से हाथ में लिया जा रहा है। 1974-75 में लगभग बीस लाख कि० वा० बिजली की क्षमता बढ़ाई जा रही है और

तीस लाख अगले वर्ष में बढ़ाई जाएगी। इस वर्ष एक करोड़ टन ज्यादा कोयला पैदा होगा। इस्पात का उत्पादन बढ़ रहा है और सरकारी क्षेत्र के इंजीनियरिंग उद्योग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अधिक रेल बैगन रोजाना चलाए जा रहे हैं।

मैं मजदूरों, किसानों, और दूसरे तबके के लोगों को बढ़ाई देता हूँ, जिन्होंने अर्थ-व्यवस्था को पायदार बनाने के सरकारी प्रोग्रामों के समर्थन में पुस्तक इरादे, साहस और राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुसार कार्य किया।

सरकार यह जानती है कि अभी आत्म-संतोष नहीं हो सकता है, क्योंकि अर्थ-व्यवस्था के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूर्ति और मांग के बीच अभी भी भारी असंतुलन है। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के बारे में भी कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता।

मुद्रा-सम्बन्धी और माली मुद्धार के लिए जो कदम उठाये गये और आर्थिक अपराधों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसे जोरों से जारी रखा जाएगा। साथ-साथ सरकार यह कोशिश करेगी कि जरूरी क्षेत्रों के इन्फ्लेक्शन में जो कमियाँ हैं, उन्हें दूर करने के लिये ठोस कदम उठाये जायें और उत्पादन बढ़ाया जायें। हम विकासशील देशों और ऐसे विकसित देशों, जिन्होंने हमारी समस्याओं को समझने का परिचय दिया है, के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक न्यायपूर्ण और बायबल अर्थव्यवस्था के विकास के लिये अपना काम जारी रखेंगे।

तेल, अनाज और रासायनिक खाद की कीमतें अचानक बढ़ जाने से हमें काफी धक्का लगा है। ग्राम जरूरत की चीजों पर असर पड़ा है और इससे जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

विदेशी मुद्रा का काफी निकासन हुआ है। 1974-75 के पहले आठ महीनों में एक्सपोर्ट अर्निंग 36 फ्रीसदी बढ़ी। फिर भी यह नुमायां बढ़ाती फारन एक्स्चेंज की कमी को पूरा करने के लिये काफी नहीं है। तेल आयात करने वाले विकासशील देशों की समस्याएँ हल करने के लिये खास प्रयास और बन्दोबस्त जरूरी है। इस मामले में तेल निर्यात करने वाले कुछ देशों ने हमारी मदद की है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ कार्रवाई की गई है। लेकिन हालात को देखते हुए ये उपाय काफी नहीं हैं। यह मानना होगा कि विकासशील देशों की अर्थ-व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है और इसे ग्लोबल पैमाने पर दुनिया के सभी देशों के अर्थपूर्ण सहयोग से पूरा करना होगा। बाइलेट्रल नैगोसियेशन्स और इंटरनेशनल फोरम्स के जरिये हम इस दिशा में उचित पहल जारी रखेंगे।

तेल का उत्पादन बढ़ाने और कोयले के इस्तेमाल पर जोर देने के अलावा, हमने तेल की खोज का काम प्राथमिकता के आधार पर शुरू कर दिया है। बम्बई हाई क्षेत्र में जो खोज की गई है उनके नतीजे बहुत ही आशाजनक हैं। सरकार ने यह फैसला किया है कि इस तेल-क्षेत्र का जल्दी से विकास किया जाए ताकि उत्पादन शुरू हो सके। ऐसी योजना बनाई जा रही है कि 1976 में उत्पादन शुरू हो जाए और अगले चार वर्षों में इस क्षेत्र से एक करोड़ टन का उत्पादन हो सके। जल व धूल दोनों ही इलाकों में तेल-उत्पादन का अविष्य बहुत आशाजनक है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ चिन्ता होना वाजबी है। योजना का एक ढांचा होता है और उद्देश्यों की एक सुसंगत प्रणाली होती है। इसके साथ तफसीली प्रोग्राम भी होता है जिससे लक्ष्यों और उनको प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधनों का पता चलता है। पांचवीं योजना के

दुनियादी ढांचे और इसके लक्ष्यों में कोई हेरफेर नहीं किया गया है। साथ ही देश और विदेश के आर्थिक क्षेत्रों में अनोखी घटनाओं को देखते हुए अपने प्रोग्राम में कुछ रद्दोबदल करने की जरूरत है। इसी बीच 1975-76 की वार्षिक योजना तैयार की जा रही है, जिसमें अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने और जरूरी क्षेत्रों—कृषि-उत्पादन, सिंचाई, रासायनिक खाद, बिजली, इस्पात, कोयला और तेल खोज में अधिक धन राशि लगाने पर बल दिया जा रहा है। यह भी प्रस्ताव है कि विकास के उन प्रोग्रामों को बढ़ाया जाए जिन से कम विकसित खण्डों और कमजोर वर्गों, जिनमें शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग भी शामिल हैं, को फायदा पहुंचे। स्माल फार्मर्स डेवलेपमेंट एजेंसी और मारजिनल फार्मर एण्ड एग्री-कलचरल लेबर, सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों और कमांड एरियास के प्रोग्रामों को बढ़ाया जा रहा है।

1974 के राष्ट्रीय प्रयासों की समीक्षा परमाणु क्षेत्र में अपनी महान तरक्की का जिक्र किये बिना पूरी नहीं होगी। 18 मई 1974 को जमीन के नीचे परमाणु विस्फोट किया गया था। मैं इस महान उपलब्धि के लिए परमाणु वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देता हूँ। हमने फिर से प्रतिज्ञा की है कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग केवल शांति के लिए ही किया जाएगा और इसके लिये सभी देशों ने हमारी सहायता की है। सरकार आर्थिक तरक्की लाने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी को महत्वपूर्ण स्थान देती रहेगी।

मुझे खुशी है कि भारत सरकार के प्रतिनिधियों और जम्मू-कश्मीर के नेताओं के साथ व्यापक रूप से हुई बातचीत के ठोस नतीजे निकले हैं। इस संबंध में सरकार जल्दी ही घोषणा करेगी। हमारी कामना है कि राष्ट्र के अभिन्न अंग के रूप में जम्मू-कश्मीर के लोग तेजी से तरक्की करे

माननीय सदस्यगण, जब राष्ट्र महान चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये जी-तोड़ कोशिश कर रहा है, यह दुःख की बात है कि कुछ जमातों के लोग जनता के संकल्प को कमजोर करने और संयुक्त तथा समान उद्देश्य, जिसकी इस वक्त बहुत जरूरत है, को निष्फल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि उनका लक्ष्य पूर्ण क्रांति लाना और भ्रष्टाचार मिटाना है लेकिन असल में नतीजा यह रहा कि हिंसा फैली और राजनीतिक और आर्थिक जीवन छिन्न-भिन्न हुआ। सरकार इस बात को पूरी तरह जानती है कि राष्ट्रीय जीवन के बहुत से क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। असल में, हमारा उद्देश्य है समाज में परिवर्तन लाना और जनजीवन के स्वभाव में सुधार लाना। लोकतंत्र की प्रणाली का यही सार है कि परिवर्तन ज्यादा से ज्यादा विचार-विमर्श और आपसी समझौते के आधार पर ही लाया जाये। जब तक क्रांति अमल कोई बेहतर तरीका सामने न रखा जाय मौजूदा व्यवस्था और संस्थाओं को छिन्न-भिन्न करने से हमारे देश की पायदारी और तरक्की को खतरा होगा।

सरकार चाहती है कि लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक पर, जो कुछ समय से आपके सामने है, विचार हो और इस वर्ष इसे अंतिम रूप दिया जाए। इससे राजनीतिक प्रशासकों और प्रशासन में भ्रष्टाचार से निपटने का कानूनी आधार मिलेगा। सरकार चुनाव-कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ जल्दी ही विचार-विमर्श करेगी। जो भी सुधार लाए जाएं वे ऐसे होने चाहिए कि जहाँ तक हो सके उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिले और उनसे हमारे संविधान में रखी गई संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली मजबूत हो।

शिक्षा के मामले में भी, सरकार ने इन्तेहान के तरीकों में सुधार लाने, सैकंडरी एजुकेशन को काम धंधों का आधार देने, उच्चतर शिक्षा

के लिए एनरोलमेंट का असूल इस्तेमाल करने और गैर-औपचारिक शिक्षा की प्रणाली लागू करने के प्रोग्राम बनाए हैं। पिछले तर्जुबे से पता चलता है कि शिक्षा के सुधार की योजनाओं में तब तक तेजी नहीं आती जब तक राज्य सरकारें, शिक्षक, माता-पिता और विद्यार्थी इन्हें स्वीकार नहीं करते। इसी बीच लाखों नौजवानों के पढ़ाई के जीवन में काफी बेचैनी देखने में आई है। राज्य सरकारों ने सुधार के कुछ प्रोग्रामों को अमल में लाने के उपाय किए हैं। हम यह चाहते हैं कि तालीम के तरीकों में अगर कोई बुनियादी तबदीली लानी है तो इसे पूरी तरह विचार-विमर्श के बाद लाया जाय।

मैं सभी तबके के लोगों से अपील करता हूँ कि वे इन बुनियादी सवालों पर संजीदगी से विचार करें, ठोस और रचनात्मक सुझाव सामने रखें और हल ढूँढने के लिए सरकार को सहयोग दें। लोकतंत्र का यही तरीका है। कोई और तरीका अपनाने से गड़बड़ फैलेगी और कोई कारआमद नतीजा न निकलेगा।

अब मैं सिक्किम की घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा। अप्रैल, 1974 में वहाँ पहली बार चुनाव हुए। सर्व-सम्मति से विधान सभा के प्रस्ताव पर 4 जुलाई, 1974 को चोग्याल की घोषणा के आधार पर नया संविधान लागू किया गया। सिक्किम की जनता की इच्छायें पूरी करने के लिये आपने सितम्बर, 1974 में संविधान संशोधन विधेयक पास किया, जिसमें भारत और सिक्किम की मित्रता को मजबूत बनाने के लिये खास व्यवस्था थी और सिक्किम के प्रतिनिधियों को हमारी संसद में स्थान दिया गया। सिक्किम की जनता को, लोकतंत्र हासिल करने की अपनी इच्छाओं और आशाओं को रफ़ता-रफ़ता पूरा करने में कामयाब होने पर हम बधाई देते हैं।

हमने, विदेशों के साथ अपने सम्बन्धों के मामले में स्वाभाविक तौर से अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के सम्बन्धों को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दिया है।

हमें दिसम्बर, 1974 में भूटान के राजा का स्वागत करने का सौभाग्य मिला। इस यात्रा से भारत और भूटान के बीच आपसी दोस्ती ज्यादा गहरी और मजबूत हुई।

पिछली मई में बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की यात्रा के दौरान, बंगला देश के साथ एक समझौता हुआ जो हमारे निकट सम्बन्धों की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसमें सीमा के उन मसलों को हल किया गया जिन पर लगभग एक पीढ़ी से कोई फैसला नहीं हो पाता था। मुझे पूरा यकीन है कि दोनों देश समझबूझ और सहयोग की उसी भावना से कोई भी मसला, जो सामने आये, सुलझाएंगे।

राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में अफ़गानिस्तान के साथ हमारा सहयोग बढ़ा है। हम अगले महीने राष्ट्रपति दाउद के आने का इन्तज़ार कर रहे हैं।

नेपाल के प्रधान मंत्री की हाल की यात्रा के दौरान, भारत-नेपाल सम्बन्धों के मुश्किल-पहलुओं पर विस्तारपूर्वक विचार हुआ। यह स्वीकार किया गया कि इसमें भारत और नेपाल दोनों का ही फायदा है कि वे आदान-प्रदान और एक दूसरे के हित को ध्यान में रखते हुए बार्डलैंडल सम्बन्धों को मजबूत बनाने की कोशिश करें।

मुझे इस बात पर खास तौर से संतोष है कि कच्चातीवू के मसले पर, पाक के मुहाने की समुद्री सीमा और श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के दर्जे के मामले में पुराने सवालों को मित्रतापूर्ण हल किया गया जिससे श्रीलंका और

भारत की दोस्ती के ताल्लुकात और मजबूत हुए ।

मालदीव और भारत के प्रधान मंत्रियों की एक दूसरे के देश की यात्रा से दोनों देशों के बीच मित्रता के सम्बन्ध मजबूत हुए ।

मारिणस के प्रधान मंत्री सर शिवसागर रामगुलाम की यात्रा से, उस देश के साथ हमारे निकट सम्बन्ध और मजबूत होने में मदद मिली है ।

अप्रैल, 1974 में बर्मा के राष्ट्रपति ने-विन की सद्भावना यात्रा से आपसी सहयोग और समझबूझ को बढ़ावा मिला है ।

पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने की दिशा में कई कदम उठाये गये हैं । प्रगति धीमी हुई है, लेकिन निराशाजनक नहीं है । दोनों देशों के बीच डाक-सेवा, टेली-कम्यूनिकेशन, यात्रा-सुविधा और व्यापार फिर से शुरू करने पर समझौते हुए हैं । हमें आशा है कि एक दूसरे से बातचीत करके और शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद दूर करने के अच्छे रवैय्ये में तेजी आएगी और पाकिस्तान यह समझने की कोशिश करेगा कि मुख्तलिफ जरूरियों से हथियार जमा करके अपने आप को फिर से लैस करना बेसूद है, क्योंकि इससे आपसी मेल-मिलाप और इस उप-महाद्वीप में पायदार अमन कायम करने में रुकावट आयेगी ।

इन्डोनेशिया के साथ कांटेनैन्टल शैल्फ बाऊन्ड्री एग्रीमेंट हुआ है । दिसम्बर, 1974 में मलयेशिया के राजा और रानी का स्वागत करने का हमें फ़ख़्र हासिल हुआ । उनकी यात्रा से हमारे दोनों देशों के बीच मित्रता और समझबूझ बढ़ने में मदद मिली ।

पूर्वी एशिया के देशों के साथ हमारे राजनीतिक और आर्थिक सम्बन्धों की रफ्तार बढ़ी है । जापान के साथ हमारे सम्बन्ध

मित्रतापूर्ण बने हुए हैं और हमारे व्यापार सम्बन्ध बढ़ते जा रहे हैं ।

जैसा आप जानते ही हैं हमारी सरकार दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार के साथ औपचारिक तथा और ज्यादा सीधा सम्बन्ध कायम करने के उपाय कर रही है ।

अरब देशों के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात बराबर की जिम्मेदारी और निकट सहयोग के आधार पर बढ़ते जा रहे हैं । हमारे और इराक, सूडान, अरब गणराज्य, संयुक्त अरब लघु गणराज्य जैसे कई अरब देशों के बीच बड़े से बड़े प्रतिनिधि मण्डलों की यात्राओं के दौरान हमने अपनी सामान्य नीतियों पर विचार-विमर्श किये और आर्थिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में कई समझौते हुए । पश्चिम एशिया की हालत गहरी चिन्ता का कारण है । पश्चिम एशिया में स्थायी शान्ति तब तक नहीं आ सकती जब तक फिलिस्तिनियों के साथ इन्साफ नहीं किया जाता और हमला करके हथियाई गई अरबों की जमीन को खाली नहीं किया जाता । हम युनाइटेड नेशन्स में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की मौजूदगी का स्वागत करते हैं ।

हमारी प्रधान मंत्री की ईरान यात्रा और ईरान के शहंशाह की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच सम्बन्ध और ज्यादा मजबूत हुए । हमने लम्बी अवधि वाली कई परियोजनाओं पर सहमति जाहिर की है जो आर्थिक और दूसरे क्षेत्रों में दोनों देशों को और निकट लाएगी ।

दुनिया में मुक्ति और स्वतन्त्रता की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना पुर्तगाल सरकार में परिवर्तन था । भारत और पुर्तगाल के बीच डिप्लोमैटिक सम्बन्ध फिर कायम करने पर एक समझौता हो गया है । हम उस देश के साथ मित्रता और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत का स्वागत करते हैं ।

स्वतंत्रता की दिशा में अफ्रीकी लोगों की कामयाबी से एक नया युग शुरू हुआ है। पुर्तगाल की कुछ कालोनियां स्वतंत्रता के द्वार तक आ पहुंची हैं और कुछ में यह प्रोसैस शुरू हो गया है। साफ तौर से इन घटनाओं का रोडेशिया के गैर-कानूनी शासन पर असर पड़ा है; हमें इस बात में कोई संदेह नहीं कि जिम्बावे में भी बहुमत शासन की स्थापना के लिये एक समझौता हो जाएगा और भेदभाव का अन्त होगा। दक्षिण अफ्रीका इस असर से बचा नहीं रह सकता। हमें पूरी उम्मीद है कि इन वाक्यात की तर्क संगति और इसके नतीजे, जिन्हें टाला नहीं जा सकता, क्लोनियलिज्म और जातिवाद के इस आखिरी गढ़ को साफ नजर आने लगेंगे और मानवीय स्वतंत्रता के दमन और अन्य प्रकार के अत्याचारों का खात्मा होगा जिन के कारण मुहज्जब दुनिया ने उन्हें सेन्सर किया है।

जाम्बिया के राष्ट्रपति डा० केनेथ कांडा और तनजानिया के उप-राष्ट्रपति श्री कवाबा की यात्राओं से भारत और उन देशों के बीच आर्थिक व तकनीकी सहयोग और मजबूत हुआ है।

आर्थिक और तकनीकी सहयोग से एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका के विकासशील देशों के साथ हम अपने सम्बन्ध मजबूत करना चाहते हैं। हमने कई क्षेत्रों में एक्सपेरटाइज का विकास किया है और हमारे यहां सिखाई हुई और तजुबेकार मानव-शक्ति का विशाल भण्डार है और इस प्रकार आर्थिक विकास की दिशा में सहयोग के लिए विकासशील मित्र देशों की मांगों को पूरा करने की हममें क्षमता है। इसी प्रकार इनमें से कई देश कई तरह से हमारी मदद कर सकते हैं। तेल की स्थिति का एक पाजिटिव पहलू यह है कि इससे विकासशील देशों में आपसी सहयोग की संभावनाएं बढ़ी हैं।

सभी राष्ट्रों के बीच मित्रता और नान-एलाइन्मेंट की हमारी नीति, और इस सब-कांटेन्ट में सामान्य स्थिति लाने का प्रोसैस तेज करने की हमारी पहल का सोवियत रूस द्वारा समर्थन किए जाने की हम बड़ी सराहना करते हैं। भारत-रूस सहयोग सभी क्षेत्रों में बढ़ रहा है।

1974 में, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन जनवादी गणराज्य और हंगरी के प्रधान मंत्रियों का स्वागत करने का हमें सौभाग्य मिला। इन नेताओं के साथ विचार-विमर्श से हमारी आपसी समझबूझ बढ़ी है।

नॉन-एलायंड मूवमेंट में और यूनाइटेड नेशन्स और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर, भारत और यूगोस्लाविया ने निकट सहयोग बनाए रखा है।

अक्टूबर, 1974 में डा० हेनरी किर्सजर की भारत यात्रा के दौरान, भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच बेहतर समझबूझ और परिपक्व सम्बन्ध की आपसी इच्छा जाहिर की गई थी। एक संयुक्त भारत-अमरीका आयोग की स्थापना की गई है, जिससे सहयोग के लिये संस्थागत आधार मिलेगा। हमें आशा है कि संयुक्त राज्य अमरीका इस सब-कांटेन्ट में आम हालात पैदा करने की दिशा में हमेशा कोशिश करता रहेगा और ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे इस पर उल्टा असर पड़े।

यूरोपियन इकनामिक कम्युनिटी विकास की समस्याओं के प्रति अधिक प्रगतिशील और उदार पालिसी अपना रही है। भारत का एक तिहाई से ज्यादा व्यापार इस कम्युनिटी के मुल्कों के साथ है और हम उनके साथ सहयोग बढ़ाने के लिये स्वाहित्मन्द हैं।

आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ हमारे सम्बन्ध एशियाई प्रश्नों पर बढ़ती हुई

समझवृद्ध के आधार पर निकट और खुशगवार बने रहे हैं। ये दोनों देश हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाए रखने की जरूरत के सम्बन्ध में, तटवर्ती राज्यों की चिन्ता से सहमत हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसे हम बहुत महत्व देते हैं।

हमारा विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक-व्यवस्था का संकट और विकासशील देशों की समस्याएँ तभी दूर होंगी जबकि सारे विश्व में शान्ति रहे और तनाव न हो।

माननीय सदस्यगण, इस अधिवेशन में आप आमदनी और खर्च के व्यौरे तथा अगले माली साल के अनुदानों की मांगों पर विचार करेंगे, जो अर्थ-व्यवस्था को और पायदार तथा एक निश्चित दिशा देने के नजरिये से महत्वपूर्ण है। नये लैजिस्लेटिव उपायों में जो आपके सामने पेश किये जायेंगे, सबसे महत्वपूर्ण वह है जिसका सम्बन्ध अर्बन लैड की सीलिंग से है। आपके सामने कई चरणों में 34 बिल विचार के लिये हैं। इनमें से कुछ का बहुत महत्व है। आपके आगे एक सम्पूर्ण और कठिन प्रोग्राम है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि तलख बहस मुवाहसा और आन्दोलनों पर राष्ट्र की शक्ति ज्ञाया न करें, बल्कि भारत की जनता को, जिनमें चुनौतियों का मुकाबला करने की पूरी क्षमता है, रचनात्मक और साहसपूर्ण नेतृत्व दें।

मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूँ।

(Text of the President's address in English)

Honourable Members, I welcome you all and summon you to another year of hard work in the service of the nation.

We begin the year on a confident note, having responded with determination to the unforeseen and stupendous challenges of the last four years. In the face of continuing rise in prices, the foremost concern of Government in 1974 was to impart a measure of stability to the economy. Government adopted a comprehensive

strategy to control inflation and this was put into operation from July, 1974.

Besides increased mobilisation of resources and economies in non-Plan expenditure, money supply was restricted through an appropriate monetary policy. — A vigorous drive was launched against economic offences like smuggling, hoarding and tax evasion and against spurious units indulging in malpractices in scarce materials. Consumer expenditure was restrained by limiting dividend incomes and impounding increases in wages and salaries and a part of additional dearness allowance. Public distribution was strengthened and arrangements were made for adequate import of foodgrains and essential raw materials and commodities. The annual plan for 1974-75 was reviewed and outlays on the core sectors were raised to boost production. Vigorous action was also taken to improve utilisation of capacity in power plants, rail transport coal production, steel plants and other public sector industries.

This concerted action began to yield results towards the end of September, 1974. Despite an unsatisfactory kharif crop caused by poor rainfall in many States, prices began to fall and there has been a weakening of the inflationary forces. The availability of essential goods has generally improved. The general outlook for the rabi crop is good.

Production in public enterprises has shown a significant rise in the first nine months of this financial year. Fourteen per cent more electricity is being produced by thermal plants and improvement of thirty-four per cent in the production of power by DVC plants merits special mention. Since shortage of power still persists in a number of States, high priority is being given to the completion of power projects. About two million K/V of power capacity is being added in 1974-75 and another three million in the coming year—Ten million tonnes more coal will be produced this year. The production is going up and public sector engineering industries are doing remarkably well. More railway wagons are being moved daily.

I congratulate workers, farmers and other sections of the people for the deter-

mination, courage and identity with national purpose shown by them in supporting the Government's programme of economic stabilisation.

Government is aware that there is no room for complacency as there are still sizable imbalances between supply and demand in several important sectors of the economy. The international economic situation is also full of uncertainties.

The monetary and fiscal measures and the action against economic offences will be continued with vigour. Simultaneously Government will intensify measures to remove limitations in the infrastructure and to increase production in vital sectors. In the international sphere, we shall continue to work for the evolution of a just and viable economic order in co-operation with developing countries as well as developed countries which have shown understanding of our problems.

We have been hit hard by the sudden and large increase in the prices of oil, food and fertilizers. Articles of common consumption have been affected and great hardship has been caused to the people. There is a very heavy draft on foreign exchange. Even a significant increase in our export earnings—in the first eight months of 1974-75, the increase was 36 per cent—is not adequate to fill the gap. Special efforts and arrangements are necessary to deal with the problems of oil-importing developing countries. Some of the oil exporting countries have helped us in this regard. There has also been some action at the international level. But these measures fall short of the needs of the situation. The severe damage caused to the economies of developing countries has to be recognized and redressed through purposeful co-operative effort on a global scale. We shall continue to take appropriate initiatives in this direction both through bilateral negotiations and in international forums.

In addition to the emphasis on increased production and use of coal, we are going ahead with oil exploration on an urgent basis. The recent discoveries in the offshore Bombay High structure are promising. Government has decided that this

oil field should be developed to the production stage with the greatest expedition. It is being planned that the first stage of production should begin in 1976 and that in another four years, the production from this area should go up to 10 million tonnes. The future outlook for production of oil from offshore and onshore area is reassuring.

There is understandably some anxiety about the Fifth Five Year Plan. A plan has a framework and a coherent system of objectives as well as a detailed programme indicating targets and the availability of resources necessary for achieving them. The basic framework of the draft Fifth Plan and its objectives remain unaltered. At the same time, the extraordinary developments in the economic sphere both external and internal, call for adjustments in the sequence and composition of detailed programmes. Meanwhile, the annual plan for 1975-76 is being prepared giving emphasis to economic stability and increased investment in crucial sectors— agricultural production, irrigation, fertilisers, power, steel, coal and oil exploration. It is also proposed to intensify development programmes benefiting the less developed regions and the weaker sections of the community including scheduled castes and scheduled tribes. Programmes under the Small Farmers Development Agency and those for Marginal Farmer and Agricultural Labour, drought prone areas and the command areas are being accelerated.

A review of the national effort in 1974 will not be complete without reference to the major advance that we made in the nuclear field—the underground experiment of 18th May, 1974. I congratulate our nuclear scientists and engineers on this signal achievement. We have reaffirmed our determination to use nuclear energy only for peaceful purposes and our reasons for undertaking the experiment have been appreciated by most countries. Government will continue to give a place of importance to science and technology as instruments of economic advancement.

I am happy that the extensive talks held between the representatives of the Government of India and the leaders of the State of Jammu and Kashmir have yielded positive results. Government will shortly

make a statement in this regard. We wish the people of Jammu and Kashmir speedy progress as an integral part of the nation.

Hon. Members, when the nation is straining every nerve to meet formidable challenges, it is regrettable that some groups have been doing every thing possible to weaken the will of the people and to sap the cohesion and unity of purpose, so vital at such times. They claim that their object is total revolution and elimination of corruption but the actual result is violence and disruption of political and economic life." Government is fully conscious of the need for reform in several spheres of national life and welcomes suggestions. Indeed, our objective is to bring about a transformation of society and to change the quality of life. It is the essence of the democratic system that changes are brought about through the widest possible discussion and agreement. Mere disruption of the existing system or institutions, with no better and workable alternative, will only endanger the stability and progress of our country.

Government is anxious that the Lokpal and Lokayukthas Bill, which has been before you for some time now, should be considered and finalised during this year. This will provide the legal framework to deal with corruption among political executives and in administration. Government will shortly discuss with the leaders of political parties proposals for changes in the electoral law. Whatever reforms are introduced should be such as will command the widest possible public support and consolidate the system of parliamentary democracy enshrined in our Constitution.

As regards education also, Government has worked out programmes for reform of the examination system, vocationalisation of secondary education, regulation of enrolment for higher education and introduction of a system of non-formal education. Previous experience shows that schemes of educational reform fail to gather momentum unless they are widely accepted by State Governments, teachers, parents and students. Meanwhile, considerable disturbance is caused in the scholastic career of millions of young people. State Govern-

ments have taken steps to implement some of the programmes of reform. We are anxious that more far-reaching changes in the educational system are introduced through the widest possible discussion.

I appeal to all sections of the people to ponder seriously over these fundamental issues, offer positive and constructive suggestions and criticisms and co-operate with the Government in working out national solutions. This is the democratic way. Any other way will lead only to chaos and disillusionment.

I may now refer to developments in Sikkim. Elections were held there for the first time in April, 1974. On the unanimous resolution of the elected Assembly, a new constitutional framework was promulgated by the Chogyal on the 4th July, 1974. Responding to the expressed wishes of the people of Sikkim, you approved a Constitution Amendment Bill in September, 1974, incorporating specific provisions for strengthening Indo-Sikkim relationship, including the representation of Sikkim in our Parliament. We congratulate the people of Sikkim on the progressive realisation of their democratic aspirations.

In our relations with the outside world, we have naturally continued to attach special importance to the consolidation of friendly relations with our neighbours.

In December, 1974, we had the privilege of welcoming the King of Bhutan. The visit served to consolidate further the traditional warm friendship between India and Bhutan.

An event of significance in our close relations with Bangladesh was the conclusion of an Agreement, during the visit of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in May last, settling the land boundary questions which had remained unresolved for nearly a generation. I feel confident that the two countries will resolve any issue which may arise in the same spirit of understanding and co-operation.

There has been increasing co-operation with Afghanistan in the political and economic fields. We look forward to the visit of President Daoud next month.

During the recent visit of the Prime Minister of Nepal, there was a detailed

exchange of views on various aspects of Indo-Nepal relations. It was recognised that it was in the interests of both India and Nepal to do their utmost to strengthen bilateral relations keeping in view, at all times, the principles of reciprocity and mutual benefit.

I am particularly gratified that the cordial relations between Sri Lanka and India were further strengthened by the amicable settlement of the long outstanding questions of Kachhativu and the maritime boundary in the waters of the Palk Bay as well as the status of persons of Indian origin in Sri Lanka.

The exchange of visits between the Prime Minister of Maldives and India strengthened the friendly relations between the two countries.

The visit of the Prime Minister of Mauritius, Sir Seewoosagur R'angoolam, helped to further strengthen our close ties with that country. *

The goodwill visit of President Ne Win of Burma in April, 1974 consolidated our mutual co-operation and understanding on bilateral and international questions.

Several steps were taken towards normalising relations with Pakistan. Progress has been slow but not discouraging. Agreements have been worked out for the resumption of postal services, telecommunications links, travel facilities and grade between the two countries. We hope that the healthy trend towards settling differences bilaterally and through peaceful means will gather momentum and that Pakistan will realise the futility of rearming itself by procuring arms from various sources, as this will hinder reconciliation and the establishment of durable peace on the sub-continent.

A continental shelf boundary Agreement as concluded with Indonesia. We were honoured to receive the King and Queen of Malaysia in December, 1974. Their visit served to underscore the friendship and understanding between our two countries.

There is a marked increase in the tempo of our political and economic relations with the countries of East Asia. With

Japan, our relations remain friendly and our trade ties are growing.

As you are aware, Government is taking steps to establish formal contacts and more direct relations with the Provisional Revolutionary Government of South Vietnam.

Our traditional ties with the Arab World have continued to be marked by solidarity and close co-operation. We have had exchange of visits at the highest level with a number of Arab countries such as Iraq, Sudan, the Arab Republic of Egypt and the United Arab Emirates, during which we have had discussions on our common policies and have entered into a number of agreements in the economic and technical fields. The situation in West Asia is a cause for grave anxiety. Lasting peace in West Asia will not be achieved until justice is assured to Palestinians and Arabs territories sized by aggression are vacated. We welcome the presence of the Palestine Liberation Organisation in the United Nations.

Our Prime Minister's visit to Iran and the visit of the Shahanshah of Iran to India contributed to the strengthening of relations between the two countries. We have agreed on a number of long term projects which should bring our countries closer in economic and other fields.

An event of great significance to the cause of liberty and freedom in the world was the change in the Government in Portugal. An Agreement has been entered into for resumption of diplomatic relations between India and Portugal. We welcome the opening of a new chapter of friendship and co-operation with that country.

In the progress of the African peoples towards independence, a new era has dawned. Some of the Portuguese colonial territories are on the threshold of independence, in others the process has begun. Apparently, these events are having an impact on the illegal regime in Rhodesia; we have no doubt that in Zimbabwe too a settlement will be reached for the establishment of majority rule and the end of discrimination. South Africa cannot remain unaffected and we sincerely hope that the logic of these events and the inevitability

ty of the outcome will be clear to this last bastion of colonialism and racialism and that there will be an end to the suppression of human liberty and other forms of persecution which have earned them the censure of the civilised world.

The visits of Dr. Kenneth Kaunda, President of Zambia and Mr. Kawawa, Vice-President of Tanzania further strengthened economic and technical co-operation between India and these countries.

He wish to strengthen our ties with the developing countries of Asia, Africa and Latin America through economic and technical co-operation. We have developed expertise in a number of fields and have a large reserve of trained and experienced man-power and thus have the capacity to respond to the requests of friendly developing countries for co-operation in economic development. Similarly many of these countries can help us in several ways. A positive aspect of the oil situation is the enormous possibilities it has opened up for mutual co-operation between developing countries.

We greatly appreciate the support given by the USSR to our policy of non-alignment and friendship among all nations and to the initiatives taken by us to expedite the process of normalisation on the sub-continent. Indo-Soviet co-operation is growing in all fields.

During 1974, we had the privilege of receiving the Prime Ministers of Bulgaria, Czechoslovakia, the GDR and Hungary. The exchange of views with these leaders has deepened our mutual understanding.

India and Yugoslavia have continued their close co-operation in the Non-aligned Movement and at the United Nations and other international forums.

During the visit of Dr. Henry Kissinger to India in October, 1974, there was expression of mutual desire for better understanding and a mature relationship between India and the United States of America. An Indo-US Joint Commission, which will provide an institutional framework for co-operation, was formed. We hope that the United States will continue to support the trend towards normalisation on the sub-

continent and will not take any steps which may adversely affect it.

The European Economic Community is taking a progressively more liberal attitude towards the problems of development. Over a third of India's trade is with the countries of the Community and we look forward to increasing co-operation with them.

Relations with Australia and New Zealand have remained close and cordial based on a growing understanding on Asian questions. Both these countries have shared the concern of the littoral States regarding the need to maintain the Indian ocean as a zone of Peace, a matter to which we attach very great importance.

We are convinced that the crisis in the international economic order and the enormous problems facing developing countries can be resolved only if there is peace and absence of tension throughout the world.

Hon'ble Members, during this Session you have to consider the Statement of Receipts and Expenditure and the Demands for Grants for the coming financial year, which is crucial from the point of view of further stabilising the economy and giving it a firm direction. Of the new legislative measures that will be presented to you, the most important one deals with the imposition of ceiling on urban land. You have as many as 34 Bills pending before you in various stages. Some of these are of far-reaching importance. You have a full and strenuous programme ahead of you. I appeal to one and all not to fritter away national energies on acrimonious controversies and agitations but to give a constructive and confident lead to the people of India, who have a proven capacity to overcome challenges.

I wish you success in your endeavours.

OBITUARY REFERENCES

MB. CHAIRMAN : I have to refer, with profound sorrow to the passing away of Shri Lalit Narayan Mishra and three of our ex-Members, Shri Ramesh Chandra Vyas, Shri J. Sivashanmugam Pillai and Shri M.J. Jamal Mo : 'den